

# मनरेगा का छत्तीसगढ़ ग्रामीण समाज के सामाजिक- आर्थिक जीवन पर प्रभाव

Hari Prakash<sup>1\*</sup> Dr. K. N. Dinesh<sup>2</sup> Dr. Suchitra Sharma<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Research Scholar, Government Vishwanath Yadav Tamaskar PG Swasashi College, Durg, Chhattisgarh

<sup>2</sup> Assistant Professor, Kalyan Post Graduation College, Bhilai Nagra, Durg, Chhattisgarh

<sup>3</sup> Assistant Professor, Government Vishwanath Yadav Tamaskar PG Swasashi College, Durg, Chhattisgarh

*सारांश – प्रस्तुत अध्ययन मनरेगा का छत्तीसगढ़ ग्रामीण समाज के सामाजिक-आर्थिक जीवन पर प्रभाव पर आधारित है। सरकार द्वारा रोजगार की समस्या को दूर करने के लिये अनेक प्रकार की योजनायें ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित कर रही है। सरकार का इस ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने का उद्देश्य यह रहता है कि सभी व्यक्ति अपनी-अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊँचा उठा सके क्योंकि एक अच्छी आय प्राप्त होने से उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार आयेगा और साथ-साथ देश-समाज से गरीबी भी दूर होगी। प्रस्तुत शोध के लिये दैव निदर्शन पद्धति के द्वारा दुर्ग जिला के धमधा तहसील के नंदनी खुंदनी गाँव के 80 उत्तरदाताओं का चयन किया गया। प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश उत्तरदाताओं को मनरेगा योजनागत लाभ का स्तर निम्न है जो ग्रामीण लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर प्रभाव डालती है।*

*कुंजी शब्द:- मनरेगा, रोजगार मूलक योजनाएँ, सामाजिक ढाँचा, न्यूनतम आवश्यकताएँ, तकनीकी शिक्षा।*

-----X-----

## प्रस्तावना:-

समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जाल इस अर्थ में क्योंकि व्यक्ति एक साथ विभिन्न सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं और इन सम्बन्धों के आधार पर एक दूसरे पर निर्भरता व्यक्त करते हैं जिससे पारस्परिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में यह बताया गया है कि गरीबी समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यमान एवं साथ ही सम्भावित अतिरिक्त श्रम शक्ति के लिए लाभदायक उच्च गुणवत्ता का रोजगार सृजित किया जाए। रोजगार में वृद्धि को सामान्य तौर पर परिवार की आय में वृद्धि के साथ देखा जाता है 1 व्यक्ति के जीवन का एकमात्र उद्देश्य यह रहता है कि वह किस प्रकार से अपने जीवन को चलाए क्योंकि जीवन निर्वाह के लिये कोई न कोई कार्य या रोजगार करना आवश्यक है। बिना रोजगार के व्यक्ति न अपना रहन-सहन, खान-पान, स्वास्थ्य, शिक्षा का विकास कर सकता है न ही अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है।

यह सभी मानवीय क्षमताओं में वृद्धि करने के मुख्य पहलू है क्योंकि जब तक व्यक्ति कोई कार्य नहीं करेगा तब तक उसे अच्छी आय प्राप्त नहीं होगी और अच्छी आय प्राप्त नहीं होने से उनकी जीवन की गुणवत्ता में कमजोरिया देखने को मिलेगी।

लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके इस आशय से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु अनेक प्रकार की विकास मूलक योजनाओं का संचालन कर रही है। उनमें से एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा 2 सितम्बर 2005 को अस्तित्व में आया और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम फरवरी 2006 को लागू हो गया। 2007-08 में इसका क्रियान्वयन 330 जिलों में तथा बाद में बढ़ाया गया और 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी 614 जिलों में इसे लागू कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कर दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गाँवों के उन परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिलाना है जिनके व्यस्क सदस्य

बेरोजगार हैं और मेहनत मजदूरी करने को तैयार हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य गाँवों में गरीबी दूर करके लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाना और उनका जीवन स्तर बेहतर बनाना है।<sup>2</sup> इस प्रकार की योजनाएं ग्रामीण गरीबी को दूर करने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जा रही हैं। हमारे देश में आर्थिक नियोजन को भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसके द्वारा आधारभूत सामाजिक ढाँचा एवं मानवीय विकास के लिए योजना तैयार करना बहुत आसान है।<sup>3</sup>

ग्रामीण भारत का संरचनात्मक स्वरूप निश्चित रूप से बदल रहा है हंलाकि ग्रामीण भारत का हृदय ज्यों का त्यों है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों में जीवन स्तर में सुधार हुआ है। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा उत्पादकता एवं रोजगार बढ़ाने में काफी प्रगति हुई है।<sup>4</sup> आठवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता निवारण हेतु गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर अधिक जोर दिया गया है। फलस्वरूप इस योजना अवधि में 90 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये ग्रामीण औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया है।<sup>5</sup>

देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने से उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में गुणवत्ता देखने को मिलेगी। किसी देश की समृद्धि उसके भौतिक साधनों एवं स्रोतों पर ही आधारित नहीं होती, बल्कि उसके समृद्धि एवं विकास के लिये मानव श्रम शक्ति का सर्वाधिक महत्व है। मानव श्रम के अभाव में भौतिक तथा अन्य साधन अपने आप में निष्क्रिय हो जाते हैं। देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में भौतिक साधनों एवं स्रोतों का समुचित उपयोग तभी संभव है जब देश-विदेश में रहने वाले लोगों के परिश्रम एवं कार्य क्षमता का सर्वाधिक उपयोग हो। प्रत्येक देश की जनसंख्या ही श्रम संगठन एवं उद्यम का महत्वपूर्ण स्रोत होता है।<sup>6</sup> आज कल हमारे देश के कई लाखों युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। बेरोजगारी के कारण आत्महत्या जैसी अप्रिय घटनायें समाज में तेजी से हो रही हैं। इस प्रकार की घटना पूरे समाज को कमजोर बना रही है। हम सरकार से यही अपेक्षा रखते हैं कि अधिक से अधिक रोजगार ग्रामीणजन तक पहुँचाये साथ ही साथ रोजगार मूलक जो योजनाये है वह, सभी बेरोजगार, गरीब असहाय, अकुशल श्रमिक के लिए लाभदायक हों।

### अध्ययन का उद्देश्य:-

प्रस्तुत शोध कार्य के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है-

- (1) उत्तरदाताओं में रोजगार के स्तर को ज्ञात करना।

- (2) उत्तरदाताओं से मनरेगा कार्यक्रम से लाभ की स्थिति को ज्ञात करना।

### तथ्य संकलन एवं उपकरण प्रविधियाँ

प्रस्तावित शोध अध्ययन में दुर्ग जिला के धमधा विकासखण्ड के ग्रामीणों से मनरेगा का छत्तीसगढ़ ग्रामीण समाज के सामाजिक-आर्थिक जीवन पर प्रभाव जानने हेतु तथ्यों का संकलन किया गया है। महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन प्रविधि के द्वारा तथ्यों का संकलन किया गया है। नंदनी खुंदनी गाँव की कुल जनसंख्या में से मतदाता सूची में से 80 उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन पद्धति से किया गया है।

तालिका क्र. 1

#### विभिन्न आयु समूहों के लोगों पर मनरेगा से लाभ प्राप्ति की स्थिति

क्र.	आयु वर्ग में	क्या आपको एवं आपके परिवार के सदस्यों को मनरेगा योजना के तहत कार्य मिला है		योग कुल आवृत्ति / प्रतिशत
		हाँ आवृत्ति / प्रतिशत	नहीं आवृत्ति / प्रतिशत	
1.	किशोरावस्था (12 वर्ष से 18 वर्ष )	1 (1.2%)	2 (2.5%)	3 (3.7%)
2.	युवावस्था (18 वर्ष से 25 वर्ष)	13 (16.2%)	19 (23.8%)	32 (40%)
3.	प्रायवस्था (25 वर्ष से 55 वर्ष)	7 (8.8%)	29 (36.3%)	36 (45.1%)
4.	वृद्धावस्था (55 वर्ष से मृत्यु तक)	3 (3.8%)	6 (7.5%)	9 (11.2%)
		<b>24</b>	<b>56</b>	<b>80</b>
		<b>30.0%</b>	<b>70%</b>	<b>100 %</b>

तालिका क्र.2

#### मनरेगा से लिंग आधारित लाभ विवरण

क्र.	लिंग	क्या आपको एवं आपके परिवार के सदस्यों को मनरेगा योजना के तहत कार्य मिला है		योग कुल आवृत्ति / प्रतिशत
		हाँ आवृत्ति / प्रतिशत	नहीं आवृत्ति / प्रतिशत	
1.	पुरुष	20 (25.0%)	35 (43.8%)	55 (68.8%)
2.	महिला	4 (5.0%)	21 (26.2%)	25 (31.2%)
		<b>24</b>	<b>56</b>	<b>80</b>
		<b>(30.0%)</b>	<b>(70.0%)</b>	<b>100%</b>

तालिका क्रं. 3

मनरेगा से जाति पर आधारित लाभ

क्र.	जाति	क्या आपको एवं आपके परिवार के सदस्यों को मनरेगा योजना के तहत कार्य मिला है		योग कुल आवृत्ति/प्रतिशत
		हाँ आवृत्ति/प्रतिशत	नहीं आवृत्ति/प्रतिशत	
1.	सामान्य	2 (2.5%)	3 (3.8%)	5 (6.2%)
2.	अनु. जाति	16 (20%)	35 (43.8%)	51 (63.8%)
3.	पिछड़ा वर्ग	6 (7.5%)	18 (22.5%)	24 (30%)
		24 (30%)	56 (70%)	80 (100%)

तालिका क्रं. 4

शिक्षा के आधार पर लाभ संबंधी जानकारी

क्र.	शिक्षा	क्या आपको एवं आपके परिवार के सदस्यों को मनरेगा योजना के तहत कार्य मिला है		योग आवृत्ति/प्रतिशत
		हाँ आवृत्ति/प्रतिशत	नहीं आवृत्ति/प्रतिशत	
1	प्राथमिक	3 (3.8%)	7 (8.8%)	10 (12.5%)
2	मिडिल	6 (7.5%)	12 (15.0%)	18 (22.5%)
3	हाई स्कूल	5 (6.2%)	18 (22.5%)	23 (28.8%)
4	हायर सेकेंडरी	3 (3.8%)	5 (6.2%)	8 (10%)
5	स्नातक तकनीकी	2 (2.5%)	3 (3.8%)	5 (6.2%)
6	स्नातक गैर तकनीकी	3 (3.8%)	4 (5.0%)	7 (8.8%)
7	स्नातकोत्तर गैर तकनीकी	0 (0.0%)	2 (2.5%)	2 (2.5%)
8	डिप्लोमा	1 (1.2%)	1 (1.2%)	2 (2.5%)
9	निरक्षर	1 (1.2%)	4 (5%)	5 (6.2%)
		24 (30%)	56 (70%)	80 (100%)

परिणाम एवं विश्लेषण

मनरेगा का विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को लाभ प्राप्त होने से संबंधित प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से मात्र 30% उत्तरदाताओं को मनरेगा से रोजगार मिला है और 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिला है। (तालिका क्रं.1) 16.2% युवाओं (18 वर्ष से 25 वर्ष) को मनरेगा योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। (तालिका क्रं. 2) उसी प्रकार पुरुष वर्ग को 25: उत्तरदाताओं को मनरेगा योजना का लाभ मिला है। तथा (तालिका क्रं.3) जाति के आधार पर अनुसूचित जाति 20.0% उत्तरदाताओं को मनरेगा योजना का लाभ मिला है तालिका क्र (4) शिक्षा के आधार पर लाभ प्राप्त होने से संबंधित प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 7.5% मिडिल स्कूल तक की

शिक्षा हासिल किये है उन्हें लाभ प्राप्त हुआ है। इस प्रकार रोजगार से वंचित लोगो की चिंतनीय स्थिति को दर्शाती है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन मनरेगा योजनाओं के लाभ से संबंधित प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीणों में मनरेगा योजनागत लाभ का स्तर बहुत ही चिंताजनक है जो ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर प्रभाव डालती है। यह एक प्रकार से दयनीय स्थिति को दर्शाती है। इस रोजगार की समस्या को दूर करने के लिये सरकार द्वारा हर संभव प्रयास करना चाहिये। रोजगार से संबंधित सभी प्रकार के सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करना चाहिये। सभी वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुये सभी को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिये, जो लोगों की आय, रहन-सहन और जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सके और साथ ही साथ लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को उपर उठा सके इस प्रकार एक सुनिश्चित भविष्य की कामना की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची: -

1. सिंह, कटार (2011) ग्रामीण विकास, रावत पब्लिकेशन पृ.251।
2. सुभाष, सेतिया.(2009) नरेगा ने खोले गाँवों में रोजगार के नए द्वार, दिसम्बर पृ.18।
3. पंत,डी.सी.(2011) भारत में ग्रामीण विकास, विश्व शरती पब्लिकेशन पृ.-35।
4. मेहर सिंह,राव.(2004) ग्रामीण समाजशास्त्र, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस अंसारी रोड दरिया गंज पृ.139।
5. पंत,डी.सी.(2011) भारत में ग्रामीण विकास, विश्व शरती पब्लिकेशन पृ.61।
6. मेहर सिंह, राव. (2004) ग्रामीण समाजशास्त्र, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस अंसारी रोड दरिया गंज पृ.198।

---

**Corresponding Author**

**Hari Prakash\***

Research Scholar, Government Vishwanath Yadav  
Tamaskar PG Swasashi College, Durg, Chhattisgarh

[harisonwani33@gmail.com](mailto:harisonwani33@gmail.com)